Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 39 , 02 नवम्बर, गुरुवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक मो. 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्प्लेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

सेना की एविएशन विंग के 31 वर्ष पूरे

नई दिल्ली। सेना की एविएशन विंग ने बुधवार को अपने 31 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर ईस्टर्न आर्मी कमांड ने सेना के सभी पायलट्स, आफिसर्स और जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि एक नवंबर 1986 को सेना की एविएशन विंग की स्थापना हुई थी। सेना की इस कमांड का मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी बतौर डायरेक्टर जनरल नियुक्त होता है और वह सेना मुख्यालय से अपने काम को संचालित करते हैं। आर्मी एविएशन विंग के नॉर्दन कमांड ने सियाचिन में चीता हेलीकॉप्टर को भेजा था। इस दौरान सेना ने अपने सर्वश्रेष्ठ पायलट्स को वहां पर भेजा और स्थितियों को परखा। साल 1986 में एयी ऑब्जर्वेशन पोस्ट यूनिट को भारतीय वायुसेना से लेकर सेना को ट्रांसफर कर दी गई थीं। सेना ने नौ हेलीकॉप्टर स्काइन के साथ ऊंचाईयों पर स्थित बैटल जोन में मौजूद ट्रूप्स को मदद की और सियाचिन के पूरे 72 किलोमीटर के इलाके में सेना के लिए हमेशा तत्पर रही।

इग्नू : सौर ऊर्जा पर दो नए सर्टिफिकेट कोर्स

नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विविद्यालय के मौजूदा कार्यवाहक कुलपति प्रो रविन्द्र कुमार का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनकी जगह अब इग्नू के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के निदेशक प्रो एसबी अरोड़ा को फिलहाल कुलपति का पदभार सौंपा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इग्नू का कुलपति बनने के दौड़ में बहुत से प्रोफेसर के नाम चल रहे हैं। इन नामों में प्रो रविन्द्र कुमार के अलावा डॉ कपिल कुमार व डॉ सुभाकांत महापात्रा के नाम है। इसके अलावा यूजीसी सदस्य प्रो सुषमा यादव का नाम भी चल रहा है। इग्नू के कार्यवाहक कुलपति प्रो कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यकाल के अंतिम दिन कहा है कि इग्नू ने शिक्षा के क्षेत्र में लोकतांत्रिक भूमिका निभाई है। बता दें कि प्रो कुमार की पहल पर ही इग्नू में सोलर जागरूकता व सोलर एप्लिकेशन इन वॉटर पम्प पर दो नए सर्टिफिकेट कोर्सेज 8 दिसम्बर को शुरू होंगे। इनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से होगी। यह कोर्सेज हिन्दी व अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, स्पैनिश भाषा में होंगे। विविद्यालय ने हाल में ही बेंगलुरु के एस व्यासा विविद्यालय के साथ करार किया है। इसके तहत सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर पीएचडी तक के योगा के कोर्सेज चलेंगे। इसकी शुरुआत जनवरी 2018 से होगी। कैम्पस में रिलायंस जीयो के नेटवर्क को डाला जा रहा है। जिससे स्टडी मटेरियल को आडियो-वीडियो फार्मेट में डाला जाएगा। यूपी के दो जेलों में इग्नू के स्टडी सेंटर शुरू : उत्तर प्रदेश के दो जेलों के कैदी अब जेल में ही इग्नू से शिक्षित हो सकेंगे। इसके लिए इग्नू ने बलरामपुर और बहराईच की जेलों मेंअपने दो अध्ययन केन्द्रों को मंगलवार को स्थापित किया है। इन जेलों में करीब 2-2 हजार कैदी हैं।

पुण्यतिथि पर याद की गयीं इंदिरा गांधी

नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पार्टी कार्यालय राजीव भवन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी 33वीं पुण्यतिथि के मौके पर मंगलवार को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का तांता लगा रहा। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति की एक सच्ची रहनुमा थीं जिन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों से भारत को विकासशील देशों में अग्रणी बनाया तथा देश से गरीबी मिटाने के लिए अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए। प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन व अन्य नेताओं ने इंदिरा जी की तस्वीर पर फूलमाला चढ़ा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के अलावा दिल्ली प्रभारी पी.सी. चाको, पूर्व विधायक हरी शंकर गुप्ता और वीर सिंह धींगान, मौहम्मद उस्मान, हरी किशन जिंदल, मदन खोरवाल, सतेन्द्र शर्मा, सेवादल मुख्य संगठक दिनेश्वर त्यागी व अब्दुल वाहिद के अलावा सभी निगम पार्षद, जिला व ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे।

देवबंद के सभी पासपोर्ट धारकों की होगी जांच

सहारनपुर। यूपी में सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों की गतिविधियों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों के पासपोर्ट की फिर से जांच करवाने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश के गृह विभाग को सहारनपुर के देवबंद इलाके के कुछ लोगों के आतंकियों के साथ संम्पर्क होने सूचना है।

गुजरात चुनाव:

कुछ कारोबारियों को छोड़ समाज का कोई भी भाग यहां खुश नहीं- राहुल गांधी

भरूच। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से तीन दिनों तक दक्षिणी गुजरात के दौरे पर हैं। कांग्रेस की नवसृजन यात्रा का यह तीसरा चरण है। राहुल इसी दौरे के दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी से मुलाकात कर सकते हैं।

जंबूसर में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश के हर प्रदेश में मेरा दौरा हो रहा है, मैं हर स्टेट में जा रहा हूं लेकिन पहली बार गुजरात में ऐसा लग रहा है कि समाज का कोई भी भाग खुश नहीं है। पूरे समाज में दुख और मुश्किल है। सिर्फ गुजरात के 5-6 कारोबारी खुश हैं, जिन्हें मोदी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में गरीबों को पानी नहीं मिलता लेकिन बड़े कारोबारियों को सारा पानी दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि गुजरात में किसान रो रहा है, कर्जा माफ करवाना चाहता है। मोदी जी ने टाटा नैनो के लिए 33000 करोड़ रुपए के लिए लोन दिया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया।

राहुल ने कहा कि सड़क पर आज नैनो नहीं दिखती है, ये गुजरात मॉडल है। गरीबों से पानी और जमीन लेकर नैनो को दिया लेकिन फायदा नहीं हुआ। गरीबों से पैसा लेकर अमीरों को पैसा देना ही गुजरात मॉडल है। गुजरात में अगर कोई युवा शिक्षा चाहता है तो उसे 10-15 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। गुजरात मॉडल के जरिए यहां के युवाओं को नहीं बल्कि चीन के युवा को रोजगार मिल रहा है। चीन में हर घंटे पचास हजार लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के

तहत 450 युवाओं को रोजगार मिलता है। हमारा मुकाबला चीन से है।

क्यों कांग्रेस के लिए जरूरी राहुल का दौरा

भरूच और सूरत दोनों ही जगहों पर पटेल समुदाय के बीच सत्ताधारी बीजेपी को लेकर भारी असंतोष है। ऐसे में राहुल के इस इलाके में दौरे को रणनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए काफी खास बताया जा रहा है। पटेल समुदाय के अलावा भरूच और सूरत के व्यापारियों में जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भी बीजेपी के खिलाफ काफी नाराजगी है। कांग्रेस दक्षिणी गुजरात में जेडीयू के नेता छोटूभाई वासवा की अगुवाई वाले दल से मुलाकात कर सीटों के बंटवारे पर अहम समझौता कर सकते हैं।

राहुल गांधी के अलावा राज्य में गुजरात चुनावों के प्रभारी अशोक गहलोत भी वासवा से पहले मुलाकात कर चुके हैं। वासवा छह बार विधायक रह चुके हैं और दिल्ली में पिछले शनिवार उन्होंने कांग्रेस अलाकमान से मुलाकात की थी। दोनों पक्ष इस बात पर राजी हुए थे कि गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी।

कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, किसानों और युवाओं पर फोकस

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में कर्मचारियों पर फोकस रखा गया है। इसके अलावा छात्रों को लैपटॉप और किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने का वायदा किया गया है। आपको बता दें कि बीते रविवार को भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, जिसके तीन दिन बाद बुधवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। ये है घोषणा पत्र की खास बातें। कांग्रेस ने मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की है।

– वहीं छोटे किसानों के लिए बिना ब्याज के कर्ज देने का वादा। हर गांव को सड़क से जोड़ने का वादा किया है।

–2 साल में अनुबंध कर्मीयों को नियमित करने वादा

– 1 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी

– सभी वादे पांच साल के अंदर पूरा करने का वादा

-एक लाख रुपये तक का लोन ब्याज मुक्त मिलेगा।

– राज्य में मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी 350 रुपये होगी।

हमेशा जवान दिखने के लिए महिलाएं अपना रहीं ये आधुनिक तरीका

नई दिल्ली। हॉलीवुड अभिनेत्रियों ने सेहतमंद रहने के लिए जो चलन शुरू किया उसे अब अमेरिका सहित ब्रिटेन की भी कई महिलाओं ने अपना लिया है। ये तरीका है बिना कुछ पौष्टिक खाए-पीए फिटनेस बरकरार रखने का। इस आधुनिक तरीके के जरिए विटामिन की ड्रिप अपनी नसों में इंजेक्ट करवाई जाती है। विटामिन शरीर को तरोताजा रखने के लिए एक बेहद आवश्यक तत्व माना जाता है। अगल-अलग फ्ल सब्जियों में विभिन्न तरीके के विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन महिलाओं का मानना है कि काम में व्यस्त रहने के कारण इस ट्रीटमेंट के जरिए विटामिन लेने काफी फायदेमंद है।

ये हैं विटामिन ट्रीटमेंट के फायदा

महिलाओं का मानना है कि IV Vitamin ट्रीटमेंट खाने-पीने की चीजें का सेवन करने के मुकाबले काफी आसान और लाभकारी है। इस ट्रीटमेंट के जरिए आपके शरीर में विटामिन की ड्रिप चढ़ाई जाती है, ठीक उसी तरह जैसे ग्लूकोस की ड्रिप किसी रोगी को चढ़ाते हैं।

इस ट्रीटमेंट को करवाने वाली कामकाजी महिलाओं का कहना है कि इससे चेहरे पर दाग-धब्बे और झुर्रियां मिटाने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं इन महिलाओं का कहना है कि इससे काम की ऊर्जा में इजाफा होता है और थकान भी कम होती है।

सिलेब्रिटीज से फेमस हुआ यह ट्रीटमेंट

आपको बदा दें कि यूं तो यह विटामिन ट्रीटमेंट अमेरिका में 50 साल पहले ही तैयार हो गया था। लेकिन हाल के कुछ सालों में कई सिलेब्रिटी ने यह ट्रीटमेंट करवाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिसके बाद यह अमेरिका समेत ब्रिटेन में भी फेमस हो गया। इसमें सिंगर रीटा ओरा, टीवी स्टार साइमन कोवेल और मॉडल सीएना मिलर जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यह ट्रीटमेंट सेहत पर बुरा असर डालता है। वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि ये सिर्फ पैसा बनाने का तरीका है। बता दें कि इस ट्रीटमेंट के एक सेशन में 450 पाउंड (करीब 40 हजार रुपये) का खर्च आता है।

ब्लू व्हेल गेम को लेकर स्कूलों को किया अलर्ट

शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों, शिक्षकों व अभिभावकों के लिए जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली। राजधानी के सरकारी, सहायता प्राप्त स्कूलों व गैर सहायता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को खतरनाक ब्लू व्हेल गेम को लेकर अलर्ट रहने को कहा गया है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गाइडलाईंस जारी की है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश दिये गये हैं।

स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल) डॉ सरोज सैन द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्कूल पेरेंट्स टीचर्स बैठक में इन गाइडलाईंस को लेकर चर्चा करें।

साथ ही विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाए। ब्लू व्हेल गेम युवाओं केलिए नियंत्रण स्तर पर साइबर रेट है। इस गेम का सबसे ज्यादा असर अवसाद ग्रस्त व अंर्तमुखी लोगों पर होता है।

शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों के लिए अलग-अलग दिशा निर्देश दिये गये हैं।

शिक्षकों के लिए जारी गाइडलाईंस में कहा गया है कि यदि कोई छात्र भिन्न तरह से व्यवहार करता है तो उसको लेकर सचेत रहें। इस संबंध में विद्यार्थी से बात करें और स्पेशल एजुकेटर की सहायता लें। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में अभिभावकों को जागरूक करें। बच्चे के शरीर पर किसी तरह के कट या चोट पर नजर रखें और इस बारे में पता करें। बच्चे के आदत में बदलाव या दोस्तों से अलग थलग पड़ने पर भी नजर रखें। विद्यार्थियों पर नजर रखकर उन्हें रचनात्मक कायरे की तरफ मोड़ें।

हिमाचल का गढ़ जीतने के लिए धूमल होंगे बीजेपी का चेहरा,

नई दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ऐलान किया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार धूमल ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। धूमल हिमाचल के दो बार सीएम रह चुके हैं। आपको बता दें कि हिमाचल में 9 नवंबर को चुनाव होना है। प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा चुनावों में अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। धूमल सुजानपुर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र की सुजानपुर विधानसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। 2012 विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के अंदर 65,006 मतदाता थे। अस्तित्व में आने के बाद इस सीट पर राज्य की दोनों बड़ी पार्टियां कब्जा जमाने में नाकाम रही थीं। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार राजिंदर सिंह ने 14,166 मतों

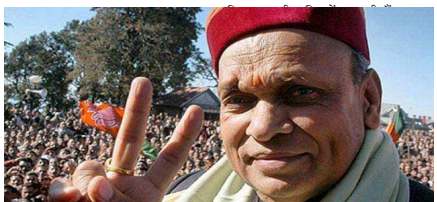

से जीत हासिल कर दोनों खेमों में खलबली मचा दी थी, लेकिन इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता और दो बार के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा से नामांकन दाखिल कर कांग्रेस और मौजूदा के प्रेम कुमार धूमल, कांग्रेस के रजिंदर राणा, बसपा के प्रवीण ठाकुर और माकपा के जोगिंदर कुमार ठाकुर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

सीबीआई ने फाइल की चॉर्जशीट, शिवराज सरकार को बड़ी राहत

व्यापमं घोटाला:

भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले में मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए राहत भरी खबर आई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भोपाल की विशेष अदालत में पेश किए गए आरोप-पत्र में कहा है कि उसने अपनी जांच में हार्ड डिस्क से किसी तरह की छेड़छाड़ होना नहीं पाया है। सीबीआई की ओर से आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि वर्ष 2013 में व्यापमं द्वारा आयोजित पीएमटी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। इस मामले में कुल 490 अभियुक्त हैं।

इनमें तीन व्यापमं के अधिकारी, तीन गिरोहबाज, 17 दलाल, 297 सॉल्वर और फायदा पाने वाले छात्रों के अलावा 170 छात्रों के परिजन हैं।

सीबीआई ने अपना आरोप-पत्र विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश करते हुए बताया कि उसने तमाम आरोपों की पड़ताल कर पुलिस द्वारा जब्त की गई हार्ड डिस्क का सीएफएसएल से परीक्षण कराया और अन्य जुटाए गए साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया है कि हार्ड डिस्क से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने नौ जुलाई 2015 को सीबीआई को व्यापमं घोटाले की जांच के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने जांच कर उन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया, जिनके खिलाफ इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में 2013 में प्रकरण दर्ज किए गए थे। इसमें वे लोग थे जो पीएमटी 2013 की परीक्षा में किसी न किसी तौर पर शामिल थे।

सीबीआई के मुताबिक, उसे आरोपियों को खोजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पता गलत थे और उन्होंने जो पता दिया, वहां ज्यादा समय तक नहीं रहे। इसके अलावा यह भी पता चला कि सॉल्वर मुख्य तौर पर चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्र थे या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान के उन स्थानों के छात्र थे, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं। इसके लिए दस लाख छात्रों तक पहुंचा गया।

सीबीआई के मुताबिक, उसे बड़ा सहयोग सॉफ्टवेयर और डाटाबेस ने किया, जिसके जरिए 42 सॉल्वर तक पहुंचा जा सका। साथ ही 11 मध्यस्थों को भी पकड़ा गया।

सीबीआई का कहना है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री (दिग्विजय सिंह) द्वारा हार्ड डिस्क से छेड़छाड़ को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के तहत भी जांच की।

यह हार्ड डिस्क इंदौर पुलिस ने बरामद की थी। हार्ड डिस्क के अलावा पेन ड्राइव और एक निजी व्यक्ति की पेन ड्राइव का हैदराबाद की सेंटल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से परीक्षण कराया गया, जिसमें पाया गया है कि हार्ड डिस्क से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। वहीं निजी व्यक्ति द्वारा पेश पेन ड्राइव में कई बातें झूठी हैं। ज्ञात हो कि

व्यापमं घोटाला एसटीएफ फिर एसआईटी और अब सीबीआई के पास जांच में है। इस प्रकरण से जुड़े 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दो हजार से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं। सीबीआई की चार्जशीट दायर किए जाने और उसमें हार्ड डिस्क से किसी तरह की छेड़छाड़ न होने का खुलासा किए जाने पर भाजपा ने खुशी जाहिर की है। प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान का कहना है कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। शिवराज सिंह चौहान पाक साफ हैं, यह एक बार फिर साबित हो गया है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं।

क्रांति समय

साधु को दिन में देखना, रात में देखना और तब साधु पर विश्वास करना -रामकृष्ण परमहंस

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने के मामले में गहरा झटका लगा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण को आश्चर्य हुआ कि आखिर संसद के जनादेश के खिलाफ कोई राज्य सरकार कैसे चुनौती दे सकती है। शीर्ष अदालत की यह टिपण्णी संविधान सम्मत है। और कोई भी संविधान का जानकर इससे असहमत नहीं हो सकता। भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत बनाए रखने के लिए ही ऐसा किया था। इसीलिए भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय होने के साथ साथ एकात्मक भी है। कानून बनाने के मसले पर केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।

समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं लेकिन अन्तत: केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होंगे। अत: इतने स्पष्ट विभाजन के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी कानून को लेकर टकराहट की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार नागरिकों के साथ-साथ किसी भी राज्य सरकार को प्राप्त है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी कानून को चुनौती दे या उसे लागू करने से इनकार कर दे। ऐसा करना संविधान विरोधी है।

शीर्ष अदालत का यह कहना जायज और संविधान सम्मत है कि ममता बनर्जी एक नागरिक के तौर पर आधार को चुनौती दे सकती हैं। ममता बनर्जी वरिष्ठ और अनुभवी राजनितिक नेता हैं। वह केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। इसलिए यह भी नहीं माना जा सकता कि उन्हें कानून और संविधान की बुनयादी समझ नहीं होगी। फिर भी केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने से पहले उनकी सरकार संविधान विषेशज्ञों से विचार-विमर्श कर लेतीं तो बेहतर होता। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करके राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। ममता का यह आचरण दूरदर्शिता वाला कदम कहा जाएगा क्योंकि इससे अदालत के साथ राज्य सरकार के अनावश्यक टकराव की नौबत नहीं आई। ममता ने यकीनन एक सुलझी हुई नेता होने का परिचय दिया है। अंत भला तो सब भला।

टकराहट की गुंजाइश

सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने के मामले में गहरा झटका लगा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण को आश्चर्य हुआ कि आखिर संसद के जनादेश के खिलाफ कोई राज्य सरकार कैसे चुनौती दे सकती है। शीर्ष अदालत की यह टिपण्णी संविधान सम्मत है। और कोई भी संविधान का जानकर इससे असहमत नहीं हो सकता। भारत में संघीय व्यवस्था है लेकिन राज्यों की तुलना में केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता मजबूत बनाए रखने के लिए ही ऐसा किया था। इसीलिए भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय होने के साथ साथ एकात्मक भी है। कानून बनाने के मसले पर केंद्र और राज्य दोनों की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची के तहत आने वाले विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं लेकिन अन्तत: केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होंगे। अत: इतने स्पष्ट विभाजन के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी कानून को लेकर टकराहट की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने का अधिकार नागरिकों के साथ-साथ किसी भी राज्य सरकार को प्राप्त है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी कानून को चुनौती दे या उसे लागू करने से इनकार कर दे। ऐसा करना संविधान विरोधी है। शीर्ष अदालत का यह कहना जायज और संविधान सम्मत है कि ममता बनर्जी एक नागरिक के तौर पर आधार को चुनौती दे सकती हैं। ममता बनर्जी वरिष्ठ और अनुभवी राजनितिक नेता हैं। वह केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। इसलिए यह भी नहीं माना जा सकता कि उन्हें कानून और संविधान की बुनयादी समझ नहीं होगी। फिर भी केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने से पहले उनकी सरकार संविधान विषेशज्ञों से विचार-विमर्श कर लेतीं तो बेहतर होता। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करके राजनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। ममता का यह आचरण दूरदर्शिता वाला कदम कहा जाएगा क्योंकि इससे अदालत के साथ राज्य सरकार के अनावश्यक टकराव की नौबत नहीं आई। ममता ने यकीनन एक सुलझी हुई नेता होने का परिचय दिया है। अंत भला तो सब भला।

सत्संग

''मुझे यह चीज नहीं चाहिए'

घटाना या विभाजन जैसी कोई चीज नहीं होती। सिर्फ जोड़ या गुणा होता है। आप जो भी कर रहे हैं, उससे बस अपने विचारों का गुणा करते जा रहे हैं, उसमें से कोई भी चीज निकाल नहीं सकते। ''मुझे यह चीज नहीं चाहिए' यह भी अपने आप में एक विचार ही है। तो आपके दिमाग में यह चलता रहता है, इसे चलने दीजिए। आपके दिमाग में कोई नई चीज नहीं आ रही है। जो चीज पहले से ही मौजूद है, बस वही घूम रही है। तो आप ध्यान में बैठे हुए हैं और विचार उठ रहे हैं, तो इस दौरान आपको कुछ करना नहीं है। शैतान आता है, तो आपको उठकर भागना नहीं है, क्योंकि आपके मन में न तो भगवान आ सकते हैं, और न ही शैतान। सिर्फ विचार ही आ सकते हैं। लेकिन पंचानबे फीसद लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। वे इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि कोई आता है, जबकि आपका मन किसी भगवान या शैतान को रिसीव करने के काबिल ही नहीं है। आपका मन सिर्फविचार पैदा करता है, और ये विचार भी उस डाटा से निकल रहे हैं, जो पहले से आपके भीतर इकट्ठे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। वही चीजें, थोड़ी बदले हुए या बढ़े-चढ़े रूप में सामने आ रही हैं। तो विचारों की जो भी प्रकृति हो, चाहे वे चित्र रूप में सामने आ रहे हों या फिल्म के रूप में, जिस भी रूप में ये आपके सामने आएं, आप इनको लेकर कुछ मत कीजिए। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके बारे में कुछ भी किए जाने की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया अस्तित्वगत होती है, न कि मनोवैज्ञानिक। आध्यात्मिकता का मतलब एक खास तरह का व्यवहार विकसित कर लेना, खास तरह की अच्छाई या खास तरीके की दयालुता विकसित कर लेना नहीं है। यह कहीं से भी आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है। यह सिर्फ खुद को समाज के काम आने लायक बनाए रखने का एक सामाजिक तरीका है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का आपके आसपास होने वाली चीजों या घटनाओं या फिर आपके मन में चल रही चीजों से कोई लेना-देना नहीं होता। आपके मन में जो चल रहा है और आपके आसपास जो चल रहा है, वो दोनों कोई अलग-अजग चीजें नहीं होतीं। जो चीजें आपके आसपास घटित हो रही हैं, वो आपके मन में इकट्ठी होती गई और फिर वे आपके मन के भीतर चक्कर काटकर आपको चकरा रही हैं।

''एजेंडा ऑफ एलायंस'

अर्ध-अलगाववादी पीडीपी के साथ राज्य में साझा सरकार बनाकर रही-सही कसर पूरी की। क्या राज्य की साझा सरकार के ''एजेंडा ऑफ एलायंस' को जानकारों ने ''विसघात का घोषणा पत्र' यों ही कहा है! आप जानते हैं कि कश्मीर में सभी अलगाववादी गुट इसका बहिष्कार करेंगे और सरकार इस आरोप से बरी हो जाएगी कि वह कश्मीरी अलगाववादियों और शेष पक्षधरों से संवाद शुरू करने की विरोधी है। सितम्बर में राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे। छिटपुट गैर-अलगाववादी गुटों को छोड़ कौन आया था उनसे मिलने! गृह मंत्री ने कश्मीर में जम्मू और लद्दाख की जनता की भावनाओं को अनदेखा कर एक बड़ा बयान दिया-भारत सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी।

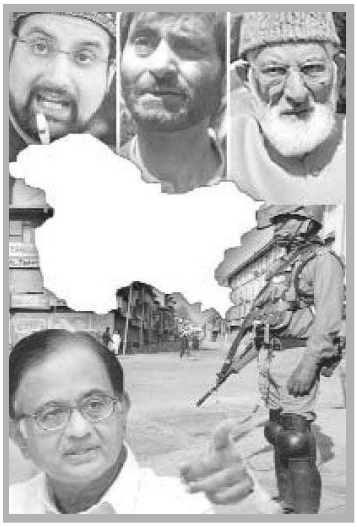

सतीश पेडणोकर

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बीती 23 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर में सभी दावेदारों से बातचीत करने, समस्या समझने और उसका समाधान सुझाने के लिएदिनेश्वर शर्मा को नये वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया है। आईबी के पूर्व निदेशक शर्मा के भारत सरकार के ''विशेष प्रतिनिधि' के रूप में कैबिनेट सचिव का भी दर्जा दिया है। लेकिन इस निर्णय को लेकर कई ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर सरकार से अपेक्षित हैं। पूछा जा सकता है कि क्या सरकार को वे सारे तयशुदा लक्ष्य प्राप्त हुए जिसके बिना सरकार कश्मीरी अलगाववादियों सहित सभी पक्षधरों से कोई गंभीर वार्ता शुरू नहीं कर रही थी? कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार विपक्ष के दबाव में आकर ऐसा कदम उठाने को विवश हुई है, और यह भी कि गुजरात में होने जा रहे विधान सभा चुनाव के चलते उसने कश्मीर को लेकर कारगर छवि दिखाने की चाल चली है।

देखा जाए तो सरकार ने शुरू से ही कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के बदले अपनी दोषपूर्ण नीतियों से उत्तरोत्तर उलझाया है, या एकता और अखंडता की दृष्टि से कमजोर ही किया है। अर्ध-अलगाववादी पीडीपी के साथ राज्य में साझा सरकार बनाकर रही-सही कसर पूरी की। क्या राज्य की साझा सरकार के ''एजेंडा ऑफ एलायंस' को जानकारों ने ''विसघात का घोषणा पत्र' यों ही कहा है! आप जानते हैं कि कश्मीर में सभी अलगाववादी गुट इसका बहिष्कार करेंगे और सरकार इस आरोप से बरी हो जाएगी कि वह कश्मीरी अलगाववादियों और शेष पक्षधरों से संवाद शुरू करने की विरोधी है।

सितम्बर में राजनाथ सिंह जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे। छिटपुट गैर-अलगाववादी गुटों को छोड़ कौन आया था उनसे मिलने! गृह मंत्री ने कश्मीर में जम्मू और लद्दाख की जनता की भावनाओं को अनदेखा कर एक बड़ा बयान दिया-भारत सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो कश्मीर के अवाम की आकांक्षाओं के खिलाफ हो। गृह मंत्री ने सोच-समझ कर ही ऐसा बयान दिया होगा क्योंकि इससे पूर्व भी विगत दो महीनों में उन्होंने कश्मीर को लेकर तीन-चार चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जैसे कश्मीर की समस्या का हम ऐसा समाधान करेंगे जिससे कश्मीर, कश्मीरियत और कश्मीर का अवाम दुष्प्रभावित नहीं होगा अर्थात केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई समाधान है, जिसे देश की जनता जानना चाहेगी। क्या है वो समाधान? उन्होंने कुछ अंतराल के बाद फिर से एक बयान दिया-हम जल्द ही कश्मीर समस्या को स्थायी रूप से हल करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से कहा,''न गोली से न गाली से, कश्मीर की समस्या सुलझेगी गले लगाने से।

'क्या भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में शर्मा की नियुक्ति को गंभीरता से लिया जाना चाहिए? ऐसा है तो क्यों सरकार ने हुर्रियत सहित तमाम पक्षधरों से सीधे संपर्क कर उन्हें संवाद के लिए आमंत्रित नहीं किया? क्यों नये वार्ताकार को निर्देश दिया गया है कि संवाद शुरू करें और अपनी रिपोर्ट पेश करें। सरकार तो समस्या जानती है, और कथित रूप से समाधान भी उसके पास है। कोई गृह मंत्री से पूछे कि कश्मीर समस्या को भाजपा के नेता कभी यह कहते हुए सिरे से नकारते हैं कि जम्मू-कश्मीर राज्य के 26 अक्टूबर, 1947 को भारत में विलय के साथ ही यह कोई समस्या ही नहीं रही; और धारा 370, अलग संविधान, अलग ध्वज, 35-ए, स्वायत्तता जैसे आपत्तिजनक प्रावधान हैं भी तो वे नेहरू और कांग्रेस की देन हैं। अब आप ही के बड़े-बड़े भाजपा नेता हैं, जिनमें गृह मंत्री के रूप में आप भी शामिल हैं, जो कह रहे हैं कि कश्मीर समस्या को हम हल करेंगे और जो हम कहते हैं करके दिखाते हैं। कृपया सरकार बताए कि क्या है कश्मीर की समस्या उनकी इस नई दृष्टि में? कश्मीरी मुसलमानों के एक बड़े अलगाववादी वर्ग की मांग है कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करना, ''निजामे मुस्तफा' (इस्लामी राष्ट्र) कायम करना। दूसरे बड़े वर्ग की मांग है ''भारत से आजादी', जिसे वे ''लाइल्ला इल्लाह' वाली व्यवस्था के रूप में व्याख्यायित करते हैं। तीसरे बड़े वर्ग की मांग है ''बृहद् स्वायत्तता ''जिसे ''लगभग आजादी' या ''लगभग पाकिस्तान' या ''लगभग भारत' के फ्रेमवर्क में पेश किया जा सकेगा। चौथे बड़े वर्ग पीडीपी की मांग है ''सेल्फरूल' (स्व-शासन), दोनों ओर के कश्मीरों का साझा शासन, विसैन्यीकरण, साझी मुद्रा, अनियंत्रित सीमाएं (पोरस बोर्डर्स), अलग-अलग विधानसभाएं आदि इत्यादि। क्या गृह मंत्री बताएंगे कि समस्या के किस पहलू को चयनित किया है सरकार ने और जिसका वह समाधान देगी? केंद्र सरकार यह भी तो भलीभांति जानती है कि कश्मीरी युवाओं का ''कट्टर' वहाबी तहरीक के तहत जिस गति से उनका तालिबानीकरण चल रहा है, जिसके चलते आईएसआईएस के झंडे फहराए जा रहे हैं, कश्मीर को सीरिया की खिलाफ त से जोड़कर अब जेहादी ब्रिगेड खुल्लमखुला गीलानी जैसे अपने इस्लामी नेताओं को भी धमका रहे हैं कि कश्मीर को इस्लामी समस्या के बदले अगर इसे वे राजनीतिक मसला कहेंगे तो वे लालचौक में उनका गला रेत देंगे। अब अलगाववादी आतंकवाद को ''गज्वाए हिंद' का रूप देने में लगे हैं, इस तय से भी तो सरकार अवगत है ही। धर्म के आधार पर ''जीनोसाइड' के शिकार लाखों विस्थापित कश्मीरी हिन्दुओं की जो मांग है कि कश्मीर घाटी में उनके लिए केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी का निर्माण हो जहां निर्बाध रूप से भारतीय संविधान लागू हो। कोई मजहबी कट्टरता न हो। सच्ची सेक्युलर राजनीतिक व्यवस्था हो। समस्या के दो और पहलू भी हैं। जम्मू की जनता और लद्दाख की जनता की भू-राजनीतिक आकांक्षाएं जिन्हें कोई भी केंद्र सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। पाकिस्तान का दूसरा पहलू तो जगजाहिर है ही। भाजपाई भी कांग्रेसियों की तरह कहते नहीं थकते कि अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में जम्मू-कश्मीर के भूभाग को छुड़ाना ही उनके साथ शेष काम है।

पृष्ठभूमि में नये वार्ताकार महोदय कौन-सी नई खोज करने के लिए भेजे जा रहे हैं? जम्मू-कश्मीर का दुर्भाग्य है कि भारतीय राज्य ने कश्मीर को लेकर हमेशा अंतर्विरोधों-विरोधाभासों की ही राजनीति की है, और वो भी कभी तुष्टीकरण के चलते और कभी उससे भी क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थो के चलते। इस दृष्टि से भाजपा सरकार की कश्मीर नीति भी कांग्रेस की नीतियों से भिन्न नहीं दिखती।

चलते चलते

''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र'

''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र' महकता रहा। इसके संस्थापक-सचिव रंजीत सिंह चौहान, अध्यक्ष कैसर खालिद और उनकी टीम ने एक बेहतर काम कर दिखाया। विभिन्न चर्चाओं के पचास से अधिक सत्र आयोजित हुए। नीरज जी की अध्यक्षता में शानदार मुशायरा हुआ, टॉम ऑल्टर को श्रद्धांजलि बतौर लालकिले का आखिरी मुशायरा नाटक दिखाया गया। पं. छन्नूलाल मिश्र और उस्ताद गुलाम मुस्तफखां का शास्त्रीय गायन हुआ।

साहित्य-संस्कृति का शानदार उत्सव था। उर्दू-हिंदी के कवि-अदीब सम्मिलित हुए। युवाओं की भागीदारी से तीन दिन तक ''इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र' महकता रहा। इसके संस्थापक-सचिव रंजीत सिंह चौहान, अध्यक्ष कैसर खालिद और उनकी टीम ने एक बेहतर काम कर दिखाया। विभिन्न चर्चाओं के पचास से अधिक सत्र आयोजित हुए। नीरज जी की अध्यक्षता में शानदार मुशायरा हुआ, टॉम ऑल्टर को श्रद्धांजलि बतौर लालकिले का आखिरी मुशायरा नाटक दिखाया गया। पं. छन्नूलाल मिश्र और उस्ताद गुलाम मुस्तफ खां का शास्त्रीय गायन हुआ। स्नेहा चक्रधर ने हिंदी गीतों पर भरतनाट्यम नृत्य दिखाया। उद्घाटन-सत्र में केंद्रीय संस्कृति मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने उत्सव को शुभकामनाएं दीं। डॉ. कर्ण सिंह ने भारतीय दशर्न की पृष्ठभूमि उजागर की। प्रो. गोपीचंद नारंग ने उर्दू-हिंदी की विरासत पर विस्तार से सोदाहरण वक्तव्य दिया।-का खास बात कही नारंग साब नै?-उनकी एक बात रह-रह कर गूंज रही है। हिंदी-उर्दू के बारे में उन्होंने कहा कि इनका रिश्ता गोश्त और नाखून जैसा है, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। उपमा यों तो ठीक है, लेकिन पिछले दो सौ साल का इतिहास देखें तो ऐसा भी हुआ कि गोश्त किसी एक भाषा का रहा और नाखून दूसरी भाषा के हो गए। ऐसा तब हुआ जब हिंदी को हिंदुओं और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मनवाने का षडयंत्र हुआ।-कब भयौ ऐसौ?-हिंदी और उर्दू भारत की लोक भाषाओं से बनी हैं। साहित्यिक रूपों में संस्कृत, अरबी और फारसी के शब्द इस्तेमाल हुए लेकिन बोलचाल में उसे हिंदी, हिंदवी, रेख्ता और उर्दू नाम दिए गए। विभाजन के बीज डाले अंग्रेजों ने। उर्दू का पहला व्याकरण लिखने वाले शायर इंशा अल्ला खां ने ही ''रानी केतकी की कहानी' लिखी थी, जिसे बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी की पहली कहानी माना। इंशा साहब कहते हैं, ''यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छुट, और न किसी बोली का मेल है न पुट'। मुझे लगता है कि हिंदी-उर्दू का नाता टायर-टयूब का है। एक की हवा निकले तो दूसरी बैठ जाए। जश्ने-अदब में टायर उर्दू का था, तो हिंदी थी टयूब।-बहुत खूब!

हर हाल में होगा हर समस्या का समाधान: उपायुक्त

झारखंड । देवघर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राजस्व, भू-हस्तांतरण, भू-अर्जन, जिला नीलाम पत्र एवं भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम उपायुक्त द्वारा आपदा प्रबंधन पदाधिकारी से जानकारी ली गई कि सारठ, सारवां, सोनारायठाढी, देवीपुर एवं करौं अंचल के राहत कोष में कितनी राशि दी गई एवं उनको निदेश दिया गया कि वे सभी अंचलाधिकारी से खर्च की गई राशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जो राशि बच गई है उसे रिटर्न कर दें; ताकि उस राशि को राज्य सरकार को लौटाया जा सकें।

सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में जिले में लगभग 53,828 लोगों को पेंशन दिया जा रहा है एवं लगभग 91: पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ हीं उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि इस मामले में राज्य में हमारा 14वाँ स्थान है एवं शेष बचे पेंशनधारियों के खाता को भी जल्द से जल्द आधार संख्या से सिडिंग करा लिया जायेगा। साथ हीं उपायुक्त द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने अंचल में सभी पेंशनधारियों को जानकारी दें कि वे खुद अपना आय प्रमाण पत्र एवं आधार सिडेड पासबुक के साथ अपना आवेदन जमा करें अन्यथा पेंशन प्राप्त करने में कठिनाईयों का भी सामना करना पड सकता है। इसके अलावे उपायुक्त द्वारा कहा गया कि जितने भी लंबित आवेदन हैं, उनका डिस्पोजल करते हुए शीघ्रातिशीघ्र उनको ऑनलाईन एक्टिवेट करायें।

वहीं उन्होंने लंबित पडे आवेदनों के निष्पादन हेतु सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा सभी अंचलों में एक-एक ऑपरेटर उपलब्ध कराये जाने की बात भी कही। साथ हीं उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि इनके माध्यम से सारे लंबित पडे आवेदनों को निष्पादित कराकर उनको ऑनलाईन कराया जाय एवं जो भी आवेदन अस्वीकृत होते हैं उनका कारण भी साथ में दर्शाया जाय। उपायुक्त द्वारा कहा गया कि सभी अंचलाधिकारियों को सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जो राशि उपलब्ध करायी गयी है, उसका व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराकर नये राशि की माँग विभाग से की जाय। साथ हीं उपायुक्त द्वारा न्यायालय संबंधी लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें जल्द से जल्द निष्पादित किये जाने का निदेश दिया गया।

भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि जिले में जितने भी एल0पी0सी0 से संबंधित लंबित मामले हैं, उनका अंचल एवं जिला प्रशासन के द्वारा मिलकर एक महिने के अंदर निस्पादन कर लिया जायेगा। वहीं उन्होंने कहा कि उपयुक्त व्यक्ति को हीं एन0ओ0सी0 प्रदान किया जायेगा वरना उपयुक्त न पाये जाने की स्थिति में उन्हें छंटनी सूची में कारण दिखाते हुए डाल दिया जायेगा।

इस दौरान भू-हस्तांतरण की समीक्षा करते हुए उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि जिले के विकास के लिए ट्रॉमा सेंटर, मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र, उद्यान महाविद्यालय, सेफ्टेज निर्माण, 33 के0बी0 के सब स्टेशन ग्रिड, प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम, स्वास्थ्य केन्द्र, सैनिक स्कूल, स्टार होटल(नन्दन पहाड), स्मार्ट कॉलोनी(देवघर), प्लास्टिक पार्क आदि का निर्माण कराये जाने हेतु भू-हस्तांतरण की आवश्यकता है। इसके तहत् भू-हस्तांतरण की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि भू-हस्तांतरण हेतु इसके भू-स्वामी को सूचना दे दी जायेगी एवं 15 दिनों के अंदर यदि कोई सहमति पत्र आता है तो ठीक है वरना उनकी सहमति मानते हुए संबंधित विभाग को भू-हस्तांतरित कर दिया जायेगा। साथ हीं उपायुक्त द्वारा पालोजोरी व सारठ के अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि पालोजोरी व सारठ के क्षेत्रों में आम भूमि, खास भूमि व गोचर भूमि की वर्तमान स्थिति का अभिलेख बनाकर उसकी सूची विभाग को उपलब्ध करायी जाय। साथ हीं उनके द्वारा म्यूटेशन एवं लगान प्राप्ति की ऑनलाईन स्थिति की जानकारी लेते हुए इसमें तेजी लाने की बात कही गयी एवं सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में लोगों द्वारा अधिक से अधिक स्वच्छता एप्प डाउनलोड करा कर उन्हें इसका प्रयोग करने हेतु प्रेरित करें।

महाकाल पर उचित पहल

आभा स्वामी

आदर्श स्थिति यही है कि धार्मिक मामलों में न्यायपालिका या सरकार का हस्तक्षेप ना हो। लेकिन आमजन में जागरूकता की कमी और स्थानीय प्रबंधकों के सही समय पर सतर्क ना होने के कारण अक्सर ऐसे दखल की जरूरत पड़ जाती है। बदलते वक्त, बढ़ती आबादी और नए प्रकार की चीजों का इस्तेमाल बढ़ने से विभिन्न् स्थलों के प्राकृतिक स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसके मद्देनजर सावधानी ना बरती जाए, तो हमारी बहुत सी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की धरोहरों का क्षय हो सकता है। ऐसी ही स्थिति उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में पैदा हुई। अतिशय चढ़ावों के कारण वहां स्थित ज्योतिर्लिंग का क्षरण होने लगा। चूंकि मंदिर प्रबंधन ने इसके प्रति सावधानी नहीं दिखाई, इसलिए एक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तब सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीमों से याचिका में कही गई बातों की जांच कराई। इनसे पुष्टि हुई कि महाकाल मंदिर की विश्व प्रसिद्ध आरती के समय जो भस्म चढ़ाई जाती है, उसका ज्योतिर्लिंग पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। ज्योतिर्लिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है, वह भी प्रदूषित और बैक्टीरिया-युक्त है। इसका खराब असर भी ज्योतिर्लिंग पर पड़ा है। वहां चढ़ाए जाने वाले दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फूलमाला भी क्षरण की वजह बन रहे हैं।

मंदिर और आराधना का संबंध आस्था से है, इसलिए अक़्सर ऐसी बातों पर लोग चुप रह जाते हैं। जिनको ये बात समझ में आती है, उन्हें भी आशंका रहती है कि उन्होंने कुछ कहा तो उससे लोगों की धार्मिक भावना आहत होगी। लेकिन यह समझने की बात है कि ऐसी चुप्पी हानिकारक है। इस कारण हमारी बहुमूल्य विरासतों को नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा हर्ष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग के संरक्षण की पहल की है। उसने मंदिर प्रशासन को आठ उपायों पर अमल करने को कहा है। इसके तहत अब ज्योतिर्लिंग का सिर्फ आरओ से स्वच्छ किए जल से ही अभिषेक किया जा सकेगा। जल की मात्रा भी 500 मिलीलीटर तक सीमित रहेगी। इसके अलावा कोर्ट ने सिर्फ प्राकृतिक फूलों के इस्तेमाल, गर्भगृह में सीमित मात्रा में श्रद्धालुओं के प्रवेश, श्रद्धालुओं के बाहर निकलने के लिए अलग द्वार बनाने जैसे निर्देश भी दिए हैं।

अब कोर्ट की भावना के अनुरूप इन उपायों पर प्रभावी ढंग से अमल किया जाना चाहिए। उचित यही होगा कि कोई भी इस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश ना करे। पिछले दिनों दिवाली के मौके पर सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी। तब कुछ हलकों से यह शिकायत की गई कि कोर्ट ने एक बड़े धार्मिक उत्सव में बेजा दखल दिया है। जबकि कोर्ट की मंशा महज दिल्ली और आसपास के लोगों को वायु प्रदूषण से बचाने की थी। महाकाल के मामले में भी उसका उद्देश्य महज इस विश्व-प्रसिद्ध तीर्थस्थल की पवित्रता बरकरार रखना है। इस महती कार्य में सबको सहभागी बनना चाहिए। महाकाल मंदिर का वैभव तभी बना रहेगा, जबकि ये पवित्र ज्योतिर्लिंग अक्षुण्ण रहे।

कैबिनेट का फैसला: यूपी में दो दर्जन ईको टूरिज्म स्थल विकसित होंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में दो दर्जन स्थानों को ईको टूरिज्म स्थल के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए जल्द ही पर्यटन विभाग और वन विभाग के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम लोक भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया।

उच्च स्तरीय सूत्रों ने बताया कि ईको टूरिज्म वाले स्थानों पर रहने और खाने की उचित व्यवस्था करने के लिए करीब सौ करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। इस खर्च के लिए भविष्य में विधानमंडल के सत्र में दोनों सदनों से पारित कराए जाने वाले सप्लीमेंटरी बजट में प्रावधान किया जाएगा।

फैसले के अनुसार प्रदेश में कुल दो दर्जन ईको टूरिज्म सेंटर विकसित होंगे। जिनमें पहले चरण में नौ ईको टूरिज्म सेंटर विकसित किए जाएंगे। ये उन स्थानों के आसपास होंगे जहां पर्यटक पहले से आते हैं। इससे वे प्रमुख स्थानों के साथ-साथ आसपास भी घूम और रुक सकेंगे।

लखनऊ और उन्नाव भी होंगे विकसित

लखनऊ में कुकरैल पिकनिक स्पाट सेंटर और उन्नाव में नबावगंज बर्ड सेंचुरी को ईको पिकनिक स्पाट के रूप में विकसित किया जाएगा। जिससे अवध घूमने आने वाले पर्यटक यहां भी रुक सकें।

बुंदेलखंड में चरखारी में विकसित होगा ईको-टूरिज्म केंद्र

इसी तरह बुंदेलखंड में चरखारी, पश्चिमी यूपी में आगरा में सूरताल (कीठम झील), पूर्वांचल में बनारस में सोनभद्र और मिर्जापुर में भी ईको टूरिज्म सेंटर विकसित होंगे। सोनभद्र में राक पेंटिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

दुधवा में फिर से बनेगी हवाई पट्टी

दुधवा नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वहां की बंद पड़ी हवाई पट्टी को दोबारा शुरू कराया जाएगा। जिससे पर्यटक सीधे वहां हेलीकाप्टर या छोटे विमानों से उतर सकें।

यूपी निकाय चुनाव:मेयर के लिए सपा के 3 प्रत्याशी

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने मेयर के लिए तीन और प्रत्याशी घोषित कर दिए। लखनऊ से मीरा वर्धन को टिकट दिया गया है जबकि आगरा सीट से राहुल चतुर्वेदी प्रत्याशी बनाए गए हैं। सपा ने फिरोजाबाद सीट पर मेयर के लिए राज नारायण मुन्ना गुप्ता को टिकट दिया है। सपा ने लखनऊ से चौंकाने वाला नाम दिया है।

मीरा वर्धन समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव के पौत्र यशोवर्धन की पत्नी हैं और समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। समाजवादी पार्टी मेयर के लिए अब तक दस सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अभी उसे छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं।

सपा ने गाजीपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में नगर पालिका परिषद के लिए प्रत्याशी तय कर दिए। गाजीपुर में नगरपालिका परिषद गाजीपुर के लिए प्रेमा सिंह, जमानियां से अनिल यादव, तथा मोहम्दाबाद- रईस अंसारी को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी मेयर के लिए अब तक दस सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अभी उसे छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं।सपा ने गाजीपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में नगर पालिका परिषद के लिए प्रत्याशी तय कर दिए। सपा ने उन्नाव नगर पालिका से ऊषा कटियार , बांगरमऊ से शहनशाह अहमद खां, गंगाघाट से सरोज शुक्ला, कुरसठ से अब्दुल रईस, फतेहपुर चौरासी से मंजू, मोहान नगर पंचायत से मो. अनवर सिद्दीकी, रसूलाबाद नगर पंचायत से नईमुद्दीन , बीघापुर सेअजय कुमार पटेल, न्योतनी से इमरान अहमद, ऊगू से योगेंद्र कुमार, नवाबगंज से रामबालक, गंजमुरादाबाद से इकबाल हसन अंसारी, मौरावां से सबीहा खां , सफीपुर से नसीम अहमद, पुरवा से मोहसिन खां उर्फ शीबू प्रत्याशी बनाया है।

भाजपा का साथ न मिला तो भासपा अकेले लड़ेगी निकाय चुनाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव अकेले भी लड़ सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी प्रदेश भाजपा प्रभारी सुनील बंसल से तीन दिन पहले बात हुई है। अगर बात बन जाती है तो बहुत अच्छा। वरना, हमारी पार्टी के अकेले चुनाव लड़ेगी। इसी क्रम में दो दिन बाद उनकी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी वार्ता होनी है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद समय-समय पर अपना असंतोष व्यक्त करने के बाबत पूछे जाने पर मंगलवार को श्री राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है। दरअसल, कुछ अफसर इस सरकार में ऐसे हैं जो पिछली सरकारों के भी वफादार रहे हैं। ऐसे ही अफसरों से उन्हें तकलीफ है।

पिछड़ों व दलितों की श्रेणियां बांट कर ही हो सरकारी नौकरियों में भर्ती : राजभर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ों और दलितों की श्रेणियां बांट कर और उनके बीच आरक्षण कोटे का नए सिरे से निर्धारण करने के बाद ही केन्द्र व राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती होनी चाहिए।

मंगलवार को यहां अपने आवास पर बुलायी गयी प्रेसवार्ता में श्री राजभर ने बताया कि केन्द्र सरकार ने एक आयोग गठित किया है, जिसमें पिछड़ों की तीन श्रेणियां पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा तथा दलितों में दलित, महादलित और अति दलित की तीन श्रेणियां तय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इन श्रेणियों के हिसाब से ही आरक्षण का कोटा भी तय किया जाना है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले दिनों श्री राजभर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिले।

श्री राजभर ने बताया कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया कि प्रदेश में यादव, यदुवंशी और ग्वाल जातियों ने पिछड़ों के आरक्षण में से अपनी आबादी के अनुपात में 39.5 प्रतिशत और जाटव, धूसिया व चमार ने एससी/एसटी के आरक्षण में से अपनी आबादी के अनुपात में 90 प्रतिशत ज्यादा आरक्षण का लाभ हासिल कर लिया है।

श्री राजभर के अनुसार दलितों में आज भी मुसहर, बांसफोर, डोम, मेस्तर, पासवान, कमकर, धोबी, पासी, खटीक, सोनकर और नट आदि जातियां आरक्षण का समुचित लाभ नहीं हासिल कर पायी हैं। इसी तरह पिछड़ों में भी राजभर, चौहान, मौर्या, कुशवाहा, प्रजापति, पाल, नाई, गौंड़, कहार, गोसाईं, बिन्द, केवट, मल्लाह, तुरही, गुप्ता, चौरसिया, लोहार, कोहार और बियार आदि जाति के लोग भी आरक्षण के लाभ से वंचित रहे हैं।

उन्नाव में आम के पेड़ से लटका मिला प्रेमी युगल का शव

उन्नाव। सफीपुर कोतवाली के परियर मार्ग पर स्थित शकहन मुसलमानन के पास स्थित आम के बगीचे में बुधवार की सुबह प्रेमी युगल का शव फंदे से लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। दुपट्टे का फंदा लगाकर प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों के शव को फंदे से उतार कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

हरदोई जिले के माधव गंज थाना क्षेत्र के बाघड़ गोत्र का रहने वाला विश्वनाथ प्रताप सिंह पुत्र राजेंद्र प्रताप सिंह का सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के गुरधरी की रहने वाली नीलम पुत्री बेचेलाल से प्रेम प्रसंग था। विश्वनाथ अक्सर नीलम के घर आया जाया करता था। दो दिन पहले नीलम घर से सामान लेने के लिए दुकान के लिए निकली थी। वह वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। घरवाले उसकी तलाश में जुटे थे। बुधवार की सुबह दोनों का शव आम के बगीचे में छतुरिया कुआं के पास लटका मिला। नीलम के दुपट्टे से एक ओर नीलम ने और दूसरी ओर विश्वनाथ ने फांसी का फंदा लगा लिया।

घटना की जानकारी होते ही सीओ सफीपुर कोतवाली प्रभारी समेत तमाम लोग मौके पर जुट गए। पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच के प्रेम प्रपंच की जानकारी उनके घर वालों को हो गई थी।

ब्लूव्हेल खेल में छात्र ने फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या

मेरठ। जानलेवा ब्लू व्हेल खेल के चक्कर में बागपत के एक छात्र ने दिल्ली में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिवार शादी में गया था और छात्र घर पर अकेला था। पुलिस को कमरे में मोबाइल फोन पर ब्ल्यूव्हेल गेम का फाइनल (टास्क) चलता मिला है। परिवार में कोहराम मचा है।

21 वर्षीय छात्र प्रिंस उर्फ राज मूलरूप से बागपत जिले में बड़ौत क्षेत्र के गांव शिकोहपुर का रहने वाला था। पिता संजीव ठेकेदार हैं।

इटावा में ट्रेन में डकैती की योजना बनाते नौ बदमाश गिरफ्तार

इटावा। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर ट्रेनों में डकैती और यात्रियों को जहरखुरानी का शिकार बनाने गिरोह के सरगना समेत नौ सदस्यों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। ये सभी इलाहाबाद-ऊधमपुर एक्सप्रेस में डकैती की योजना बना रहे थे। इनके कब्जे से तमंचे, चाकू, मोबाइल व नकदी भी बरामद हुई है।

एसओ जीआरपी इटावा विजय सिंह ने बुधवार को बताया कि पकड़े गए बदमाशों में गैंग लीडर वीरेश यादव निवासी ग्राम तसालपुर कलां थाना क्वारसी जिला अलीगढ़, अनिल यादव निवासी खेर रोड इंदिरानगर थाना देहली गेट, संजय नाई निवासी इंदिरानगर, मुकीम निवासी नौगवां अर्जुननगर थाना लोधा, मनोहर जाटव निवासी ग्राम नगला बरी थाना विजयगढ़, विजय निवासी नगला महताब थाना देहली गेट सत्तार निवासी नगला तालसपुर थाना देहली गेट, धर्मवीर उर्फ धर्मेन्द्र निवासी इंदिरानगर, बृजेंद्र निवासी ग्राम नगला मेहताब थाना देहली गेट जिला अलीगढ़ शामिल हैं। इनके कब्जे से लूट का सामान भी बरामद हुआ है।

एसओ ने बताया कि अपर पुलिस महानिदेशक वीके मौर्य व पुलिस महानिरीक्षक रेलवे इलाहाबाद बीआर मीना के निर्देश पर ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी रेलवे आगरा नितिन तिवारी द्वारा गठित टीम में उनके साथ एसओ जीआरपी टूंडला राजकमल, एसआई रविंद्र बाबू, एसआई देवेंद्र कुमार शर्मा, सर्विलांस सेल जीआरपी आगरा में तैनात कांस्टेबिल चंद्रकांत सिंह, हेडकांस्टेबल बेचे लाल, कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, आलोक गौतम, अनुज कुमार शामिल हैं, सभी मंगलवार देर रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक सर्च अभियान चला रहे थे, तभी ट्रेन में डकैती की योजना बना रहे इन नौ बदमाशों को पकड़ा गया। सभी बदमाश अलीगढ़ क्षेत्र के शातिर अपराधी हैं जो अलीगढ़ के कई थानों से जेल जा चुके हैं। अलीगढ़ से कानपुर तक करते थे वारदातें

इटावा। एसओ ने बताया कि बदमाशों का कार्यक्षेत्र अलीगढ़ से कानपुर तक का है। ये सभी ट्रेनों के साथ प्राइवेट बसों व टेम्पो में भी वारदातें करते थे गैंग लीडर वीरेश यादव सभी सदस्यों का खर्च उठाता है। वारदात के बाद सभी हिस्सा बांट करते हैं। यह गैंग अलीगढ़ से मूरी व कालका मेल में सवार होकर लूटपाट करता था। सभी बदमाशों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। वीरेश यादव 15 साल से अपराध की दुनिया में है और वह कई बार जेल भी जा चुका है।

सिक्किम की तरह बिहार भी बनेगा पूर्ण जैविक राज्य: डॉ. प्रेम

पटना.कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि सिक्किम की तरह ही बिहार को भी पूर्ण जैविक राज्य बनेगा। इसके लिए पंचवर्षीय कृषि रोड मैप के माध्यम से जैविक कॉरीडोर योजना शुरू की जा रही है। 9 नवंबर को राष्ट्रपति इस योजना की शुरूआत करेंगे। गंगा के दोनों किनारे के गांवों को जैविक गांव बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक सर्टिफिकेशन के लिए बुधवार को विभागीय सभागार में सिक्किम के साथ बिहार का करार होने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में चरणबद्ध तरीके से जैविक ग्राम बनाया जाएगा। अभी बिहार में कुछ जैविक खेती तो हो रही है, लेकिन सर्टिफिकेशन की सुविधा नहीं है। देश में सिक्किम पहला राज्य है, जहां पूरी तरह जैविक खेती ही होती है। करार के बाद सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा प्रमाणित पत्र किसानों को बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से मिलेगा। पटना से नालंदा तक एनएच के दोनों किनारों एवं पटना से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरीडोर के रूप में चिह्नित किया गया है। देश के हर थाली में बिहार का एक व्यंजन पहुंचाने के लिए जैविक खेती से सफलता मिलेगी। कृषि उत्पादन आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने कहा कि दूसरी हरित क्रांति पूर्वी भारत से होनी है। इसमें बिहार की बड़ी भूमिका होगी। जैविक खेती की दिशा में बिहार आगे बढ़ेगा। प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने कहा कि सिक्किम में 2003 से जैविक खेती शुरू हुई। 2016 में सिक्किम पूर्ण जैविक राज्य घोषित हुआ।

एसएसओसीए की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. यशोदा प्रधान एवं बीएसएसओसीए के निदेशक बेंकटेश नारायण सिंह द्वारा एकरारनामा पर हस्ताक्षर किया गया। मौके पर कृषि निदेशक हिमांश कुमार राय, सुधीर गिरि, आदित्य नारायण राय, गुलाब यादव, अनिल झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। संचालन संयुक्त निदेशक अशोक प्रसाद व संचालन संजय कुमार ने किया। जैविक खेती करने वाले किसानों का निबंधन सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (एसएसओसीए) में होगा। यहां से दिया गया प्रमाणपत्र बिहार बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (बीएसएसओसीए) के माध्यम से मिलेगा। एसएसओसीए के निरीक्षक बिहार में प्रतिनियुक्त होंगे।

जहरीले फल खाने से तीन बच्चों की मौत,छाया मातम

जमुई। बिहार के जमुई जिले के सोनो के दहियारी गांव के दो तथा खैरा के मांगोंबंदर गांव के एक बच्ची की मौत जहरीली फल खाने से हो गई। मिली जानकारी के अनुसार छठ महापर्व के दौरान 27 अक्टूबर को बच्चियों ने जंगली फल खाया था। फल खाने के बाद इन लोगों की तबियत बिगड़ गई। परिवार के लोगों ने अपने-अपने बच्चियों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पताल में दाखिल कराया।

मांगोबंदर निवासी गोपाल यादव की 4 वर्षीय पुत्री अनिशा का इलाज देवघर अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान ही 30 अक्टूबर की शाम उसकी मौत हो गई। जबकि दहियारी गांव निवासी भोला यादव की पुत्री अनुप्रिया का इलाज झाझा में चल रह था। 31 अक्टूबर को उसने भी दम तोड़ दिया। वहीं दहियारी के ही दिलीप यादव की 5 वर्षीय पुत्री खुशबु कुमारी का इलाज जमुई के अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान मंगलवार रात 8 बजे उसकी मौत हो गई।

चिकित्सकों के अनुसार जहरीली फल खाने से फूड प्वाइजनिंग हो गया था। पूरे शरीर में जहर फैल गया था। लगातार बचाने के लिए स्लाइन चढ़ाया जा रहा था। जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही थी। शरीर में जहर फैलने के कारण बच्चियों की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार छठ पर्व के दौरान दहियारी में भोला यादव के यहां छठ हो रहा था। मांगोबंदर की रहने वाली अनिशा भी छठ पर्व में शामिल होने के लिए परिवार के साथ दहियारी गई थी। रिश्ते में अनिशा दहियारी निवासी अनुप्रिया की ममेरी बहन है। छठ पर्व के मौके पर तीनों बच्चियां पास के बहियार में गई थी एक पेड़ से इन लोगों ने फल तोड़ कर खाया था। जब तीनों घर पहुंची तो इन लोगों का तबियत बिगड़ गया। शरीर का रंग भी बदलने लगा।

रेलवे के फरमान के साथ ही इतिहास बनी 156 साल से चल रही श्रमिक ट्रेन

पटना। जमालपुर रेल कारखाना के स्थापना के साथ वहां के कर्मचारियों के लिए चलने वाली श्रमिक ट्रेन मंगलवार से इतिहास बन गयी। मंगलवार की शाम 6.25 बजे यह ट्रेन कारखाना के कर्मचारियों को लेकर अपनी अंतिम सफर पर निकली। इस लेटलतीफ ट्रेन से घर जाने वाले करखनिया यात्रियों को आज समय पर घर पहुचने की नहीं दूसरे दिन से ड्यूटी आने की चिंता थी। क्योंकि रेलवे बोर्ड के निर्णय के अनुसार लगभग 156 साल से चल रही इस ट्रेन की सेवा 1 नवंबर से बंद कर दी गई है।

कारखाना के पुराने कर्मचारियों के अनुसार 8 फरवरी 1862 में जमालपुर रेल कारखाना की स्थापना के समय से ही इस ट्रेन का परिचालन हो रहा है। जमालपुर रेल कारखाना का निर्माण तब हुआ था जब पूर्वी भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी रेलवे का विस्तार कर रही थी। लिहाजा रेलवे बोर्ड के फैसले से सिर्फ एक ट्रेन की सेवा ही बंद नहीं हुई बल्कि बिहार के साथ साथ पूर्वी भारत में रेलवे के विकास की एक जीवंत निशानी हमेशा के लिए इतिहास बन गई है। रेल कारखाना के कर्मचारियों का दबाव है कि इस ट्रेन की सेवा जारी रखी जाय या इसी समय में दूसरी पैसेंजर ट्रेन दी जाय जिसमें टोकन पास मान्य हो।

डीआरएम मोहित सिन्हा ने बताया कि अब कारखाना में कर्मचारियों की संख्या महज 518 रह गई है। इतने कर्मचारियों के लिए दो-दो ट्रेन चलाना निश्चित रूप से रेलवे के लिए नुकसान था। इसलिए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। इसपर विमर्श हो रहा है कि श्रमिक ट्रेन के समय के आसपास चलने वाली दूसरी पैसेंजर ट्रेन का उन जगहों पर स्टॉपेज दिया जाय जहां श्रमिक ट्रेन रुकती थी।

ड्राइवर और गार्ड भी इमोशनल, बोले- आज अच्छा नहीं लग रहा

भागलपुर। श्रमिक ट्रेन के ड्राइवर संजय कुमार मंडल और गार्ड राकेश कुमार आज अंतिम बार श्रमिक ट्रेन चला रहे थे। दोनों ने कहा- फैसला बोर्ड का है, क्यों और कैसे का जवाब तो नहीं दे सकते लेकिन आज अच्छा नहीं लग रहा है। संजय ने बताया 2002 से मैं इस ट्रेन को चला रहा हूं।

हमने टोकन के लिए जो त्याग किया उसका क्या मिलेगा

ट्रेन में यात्रा कर रहे रेल कारखाना कर्मी यह तो मानते हैं कि यह रेलवे के लिए घाटे की ट्रेन है लेकिन अपने घाटे का भी हिसाब चाहते हैं। महरणा निवासी कारखानाकर्मी रामविलास यादव, अभयपुर निवासी रामप्रकाश रजक और रामस्वरूप पंडित, पाटम के प्रेम कुमार ने कहा कि वे लोग 198 5 से इसी ट्रेन से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रेन बंद हो लेकिन उन्हें वैकल्पिक साधन मिले।

पटना में पांच स्थानों पर लगेंगे एयर क्वालिटी मॉनिटर

पटना। उपमुख्यमंत्रीसुशील कुमार मोदी ने कहा कि दिनोंदिन गंभीर होती प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नई तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाना होगा। राजधानी में पांच स्थानों पर वायु गुणवत्ता को मापने की मशीन लगाई जाएगी। साथ ही मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में भी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वे मंगलवार को सेंटर फॉर इनवायरमेंट एंड इनर्जी डेवलपमेंट (सीड) द्वारा वायु प्रदूषण पर राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाड़े के मौसम में पटना में वायु प्रदूषण की स्थिति काफी चिंताजनक हो जाती है। अक्टूबर से मार्च के बीच वायु में एसपीएम की मात्रा 100 से 300 माइक्रोग्राम घनमीटर तक पहुंच जाती है, जबकि 60 माइक्रोग्राम घनमीटर ही होना चाहिए।

सीवरेजके पानी का उपचार के बाद सिंचाई में होगा उपयोग : मोदीने कहा कि जल्द ही सीवरेज के पानी को उपचार के बाद भी गंगा में बहाने की बजाय उसका उपयोग खेती में किया जाएगा। सेमिनार को आद्री के सदस्य सचिव शैबाल गुप्ता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आलोक कुमार, शक्ति सस्टेनेबल इनर्जी फाउंडेशन के कुणाल शर्मा, सीड के सीईओ रमापति कुमार, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राजीव उपाध्याय आदि ने भी संबोधित किया। सेमिनार में यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान और झारखंड के मंत्री सरयू राय का वीडियो संदेश दिखाया गया। इस सेमिनार में बिहार, झारखंड और यूपी के प्रतिनिधि मौजूद थे।

पटनाउपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी ने ट्वीट कर राहुल गांधी से पूछा- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद कालेधन की जांच क्यों टलती रही इसके पीछे क्या मकसद था राहुल गांधी यह भूल जाते हैं कि यूपीए सरकार के 10 साल में हुए लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और कालेधन की बड़ी राशि का विदेशी बैंकों में जमा होना ही अर्थव्यवस्था के जहाज के लिए सबसे बड़ा तारपीडो साबित हुआ था।

ट्रक-जीप की टक्कर से 4 मरे, पहले पिता और फिर 24 घंटे बाद बेटे की हुई मौत

रफीगंज. अंधेरे में जीप नहीं दिखने की वजह से सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही जीप पर सवार चार लोगों की मौत हो गई। जबकि, तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे रफीगंज-शिवगंज पथ के खड़वां मोड़ पर हुई। मृतकों में मठ पड़रिया गांव के रहने वाले 23 वर्षीय चंदन सिंह, 32 वर्षीय चंचल सिंह, 32 वर्षीय संजीत सिंह व 24 वर्षीय सियाराम सिंह शामिल हैं। घायलों में उसी गांव के जयप्रकाश उर्फ विशाल, प्रमोद सिंह व जीप चालक जितेन्द्र सिंह शामिल हैं। सूचना पाकर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भिजवाया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया गया है। इधर, मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की।

हादसे में पहले पिता की मौत के 24 घंटे बाद पुत्र ने दम तोड़ा

बखोरापुर मंदिर में पूजा कर लौटते वक्त मथवलिया मोड़ के समीप सड़क दुर्घटना में मरे मुन्ना सोनी के दो वर्षीय पुत्र आयुष सोनी की सोमवार की रात पटना में पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुन्ना सोनी आरा शहर के तरी मुहल्ला के निवासी थे। आरा-बड़हरा रोड पर सड़क दुर्घटना में सोमवार को ही उनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि सोमवार को मुन्ना सोनी अपने परिवार व तरी मुहल्ला निवासी ससुराल वालों के साथ ऑटो पर बैठकर बखोरापुर से आरा लौट रहे थे।

22 साल बाद आया फैसला, 9 साल के बच्चे की हत्या में 3 को आजीवन कारावास

मुजफ्फरपुर. मुशहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर जगदीश गांव निवासी 9 वर्षीय रंजीत महतो की हत्या के मामले में मंगलवार को 22 साल बाद फैसला आया। एडीजे-11 डॉ. राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने तीनों दोषियों मुशहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर जगदीश गांव निवासी उपेंद्र राम, बेला थाना क्षेत्र के धीरनपट्टी गांव निवासी राजेश राम व मनोज राम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी मृतक रंजीत के पिता चुलहाई महतो ने मुशहरी थाने में दर्ज कराई थी। 19 सितंबर 1995 की शाम से लापता बच्चे रंजीत का शव रोहुआ आपूछ इलाके में पाया गया था।

मैट्रिक और इंटर में 3.87 लाख कम हुए रजिस्ट्रेशन

पटना। इंटरमीडिएट के बाद अब मैट्रिक में भी रजिस्ट्रेशन की संख्या कम हो गयी है। इंटर और मैट्रिक दोनों की बात करें तो 3.87 लाख रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। इंटर में जहां इस बार 2.62 लाख रजिस्ट्रेशन कम हुए वहीं मैट्रिक में अबतक 1.25 लाख रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मानें तो मैट्रिक में अभी तक 13 लाख 40 हजार छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन अभी एजेंसी से पूरी रिपोर्ट नहीं आ पायी है। एजेंसी से रिपोर्ट आने के बाद कुछ और रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ेगी। मैट्रिक और इंटर में रजिस्ट्रेशन बढ़े, इसके लिए बिहार बोर्ड ने तीन बार रजिस्ट्रेशन की तिथि भी बढ़ाई, लेकिन इसके बाद भी वैसी बढ़ोतरी नहीं हो पायी।

एजेंसी कर रही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन के लिए एजेंसी को लगाया गया है। प्रदेशभर के नौ में से आठ प्रमंडलों में एक एजेंसी रजिस्ट्रेशन करवा रही है तो वहीं कोसी प्रमंडल में दूसरी एजेंसी को काम सौंपा गया है। ये दोनों एजेंसियों के ऊपर नाइसा एजेंसी कंट्रोल कर रही है। एजेंसी से रिपोर्ट आने के बाद कुछ और रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ेगी। मैट्रिक और इंटर में रजिस्ट्रेशन बढ़े, इसके लिए बिहार बोर्ड ने तीन बार रजिस्ट्रेशन की तिथि भी बढ़ाई, लेकिन इसके बाद भी वैसी बढ़ोतरी नहीं हो पायी। एजेंसी हर प्रमंडल के जिलों में कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से विद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवा रही है।

वर्ल्ड रो पावर लिफ्फटिंग में सूरत की रोमा ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया

क्रांति समय संवाददाता, सूरत। गुजरात के सूरत शहर की रहने वाली रोमा विरेन शाह ने वर्ल्ड रो पावर लिफटिंग फेडरेशन द्वारा 27 अक्टूबर को रशिया के मास्को में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफटिंग चैम्पीयनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर सूरत सहित समपूर्ण भारत की शान बढ़ाया है। रोमा भारत की पहली महिला है जिसने इतनी कम उम्र में ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में विश्व के अलग-अलग 32 देशों के 22000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था।

सूरत। सूरत के वड़ताल में स्थित स्वामी नारायण मंदिर में बुधवार को 36 मुमुक्षुओं ने सन्यास की दीक्षा ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वामी नारयण संप्रदाय के धर्म गुरुओ सहित अनुयायी उपस्थित रहे।

सूरत। देव उठनी एकादशी के साथ ही बैड बाजे और बारात का शिलशिला शुरु हो गया। शहर के अठवा लाइंस से गुजरती हुई बारात।

सूरत। शहर के मगदल्ला रोड़ पर चलती हुई ट्रक के डीजल टेंक मे लिकेज के कारण अचानक आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक ट्रक पुरी तरह से धू-धू कर जलने लगी।

सूरत। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागु होते ही चुनाव के दौरान जगह-जगह वाहनों की पुलिस चौकिंग शुरु हो गई।

गोपीपुरा में अधेड़ के जेब से बदमाश 6 हजार चुराकर फरार

क्रांति समय संवाददाता, सूरत। गोपीपुरा मेन रोड पर से बाइक लेकर गुजर रहे एक अधेड़ की बाइक के साथ अनजान चोर उच्चको ने अपनी बाइक की भिडन्त कर झगड़ा कर जेब से 6 हजार रुपए चुराकर फरार हो गए होने का मामला सामने आया है । अथवालाइन्स पुलिस के अनुसार चोकबाजार के नानावट स्थित शाहपोर के अल फे इज पैलेस निवासीअब्दुल रहमान अब्दुल करीम व्होरा (53 वर्ष) व्यापारी है । 26 अक्टूबर की दोपहर अधेड़ अपनी बाइक लेकर गोपीपुरा मेन रोड पर से गुजर रहे थे इसी दौरान सामने से एक बाइक पर सवार होकर आए बदमाशो ने अपनी बाइक पीड़ित की बाइक के साथ भिडन्त कर अधेड़ के साथ झगड़ा कर जेब से 6 हजार रुपए चुराकर फरार हो गए । हादसे के चलते अधेड़ की शिकायत पर अथवालाइन्स पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू की है ।

लालगेट की बैंक से 70 हजार की चोरी

सूरत। लालगेट के भागलतलाव स्थित बैंक ऑफ बरोडा में काम के सिलसिले में आये अडाजन के अधेड़ की बेग से अनजान व्यक्ति नगद 70 हजार रुपए चुराकर फरार हो गए होने का मामला सामने आया है।

लालगेट पुलिस के अनुसार अडाजन के पाल रोड स्थित माउन्ट एवन्यू अपार्टमेंट निवासी शिवाजी भाई बालाजी भाई मोरे (53 वर्ष) नौकरी कर परिवार का गुजारा करते है । 31 अक्टूबर की दोपहर शिवाजी भाई भागलतलाव शाखा की बैंक ऑफ बरोडा में काम के सिलसिले में गए थे और बैंक में क्लीयरिंग काउंटर पर आरटीजीएस तथा क्लीयरिंग के चैक पर बैंक ऑफ बरोडा की सिक्के मारकर काउंटर पर दे रहे थे इसी दौरान शिवाजी भाई ने क्लीयरिंग काउन्टर के पास रख्खी 70 हाजर की नगद भरी काले रंग की हेण्ड बेग से अनजान चोर उच्चका पैसे लेकर फरार हो गया। हादसे के चलते शिवाजी भाई की शिकायत पर लालगेट पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू की है ।

सूरत। शहर में आयोजित होने वाले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। शहर के वराछा क्षेत्र स्थित विशाल मैदान में राहुल गांधी की जनसभा के लिए तैयारिया करते कार्यकर्ता।

हार्दिक के कांग्रेस से जुड़ने पर भाजपा को ओबीसी वोट मिलने की उम्मीद

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच शह-मात का खेल शुरू हो गया है। पास नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस को समर्थन देने का संकेत दे चुके है। जिसके बाद भाजपा की उम्मीद बढ़ है कि यदि हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ जाते हैं तो बड़ी संख्या में ओबीसी वोट छिटकर भाजपा के खाते में आ सकते हैं। ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर के साथ आने से गदगद कांग्रेस अब पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी को अपने साथ जोड़ने का भरसक प्रयास कर रही है। जिग्नेश मेवाणी ने फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं की है, परंतु हार्दिक पटेल साफ कर चुके हैं कि वे किसी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। मतलब हार्दिक पटेल पटेल अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस को समर्थन का संकेत दे चुके हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए एक म्यान में दो तलवारें रखना भारी पड़ रहा है। हार्दिक पटेल ओबीसी में आरक्षण

चाहते हैं, जबकि अल्पेश ठाकोर इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भाजपा का मानना है कि हार्दिक पटेल यदि कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करते हैं तो बड़ी संख्या में ओबीसी वोट उसके खाते में आ सकते हैं। भाजपा की परंपरागत वोट बैंक माने जाते पाटीदारों को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस हार्दिक पटेल का साथ चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस को यह डर भी सता रहा है कि यदि पाटीदारों का ओबीसी में आरक्षण का वादा करती है तो उसकी परंपरागत ओबीसी वोट बैंक नाराज हो सकती है। पाटीदारों को आरक्षण देने के बारे में कांग्रेस गोल गोल बातें कर रही हैं। भाजपा को उम्मीद है कि किसी एक को खुश करने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। यदि कांग्रेस पाटीदारों को आरक्षण देने का वादा नहीं करती है तो उसके वोट उसे मिलने से रहे। कल तक भाजपा के लिए सिरदर्द रहे हार्दिक पटेल अब कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन गए हैं। भाजपा ने जो संभव था वह पाटीदारों को दे दिया है। लेकिन ओबीसी कोटे में पाटीदारों को शामिल करना कानूनी रूप से संभव नहीं है। कांग्रेस ने भी पाटीदारों को किस प्रकार आरक्षण देगी इसकी स्पष्टता नहीं की। भाजपा ने अब यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस ने भी पाटीदारों को ओबीसी में आरक्षण देने का वादा कहां किया है। इस मुद्दे के साथ ही भाजपा ने हार्दिक पटेल पाटीदारों को गुमराह करता होने की आवाज बुलंद कर दी है। भाजपा के गणित के मुताबिक यदि हार्दिक पटेल कांग्रेस को समर्थन का ऐलान करते हैं तो पाटीदारों के वोट से होनेवाले नुकसान की भरपाई वह नाराज ओबीसी वोटों से कर सकती है।

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया

जूनागढ़ (ईएमएस)। शहर की एक युवती को प्रेमजाल में फांसकर उसे शादी का झांसा देकर वेरावल का एक शख्स उसे होटल में ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसका शख्स ने वीडियो बनाया और उसे सिगरेट से जलाकर रु. 1.64 लाख भी ऐंठ लिए। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अल्ताफ फकीर नामक शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की कवायद तेज की है। सूत्रों के मुताबिक जूनागढ़ के बुंदेला चौक क्षेत्र में रहनेवाली 24 साल की एक युवती का एकाद साल पहले वेरावल के अल्ताफ इकबाल शाहमदार के साथ मोबाइल के जरिए परिचय हुआ था।

गुजरात चुनाव में आतंकवाद को लेकर भाजपा -कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप

अहमद पटेल ने निकाला बीजेपी नेता का आंतकी कनेक्शन

अहमदाबाद (ईएमएस)। पीएम मोदी के गृहराज्य गुजरात में चुनावों की तारीख की घोषणा होने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस एक-दूसरे पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को रोजगार-किसान-पाटीदार के मुद्दे पर घेरना चाहती है तो वहीं बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। लेकिन इस गुजरात चुनाव में आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कांग्रेस नेता अहमद पटेल पर आरोप लगाया था, अब अहमद पटेल ने भी भाजपा पर आंतकवाद को लेकर पलटवार किया है। गुजरात सीएम विजय रूपाणी ने अहमद पटेल पर आरोप लगाया था कि गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते की ओर गिरफ्तार आईएस आतंकी उनके संरक्षण वाले अस्पताल में नौकरी करते थे। मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अहमद पटेल से इस्तीफा मांगा है। इसके बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने बुधवार को एक रैली के दौरान कहा कि भोपाल में जो आतंकी गिरफ्तार हुए थे, उनमें से एक सदस्य का सीधा कनेक्शन बीजेपी के साथ था। आपको बता दें कि फरवरी में मप्र एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से एक बीजेपी आईटी सेल का सदस्य ध्रुव सक्सेना था। इन सभी का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान जांच एजेंसी आईएसआई से था। उस दौरान उस व्यक्ति कई फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिनमें वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच पर खड़ा हुआ था। गौरतलब है कि हाल ही में गुजरात एटीएस ने आईएस के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, अस्पताल की ओर से कहा गया था कि अहमद पटेल ने 2014 में इस्तीफा दे दिया था। खुद अहमद पटेल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। साफ है कि जिस तरह से गुजरात में चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बुधवार को मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात में सिर्फ 5-6 उद्योगपतियों की ही मदद की है जबकि किसान और गरीब हो रहा है।

विश्व उमिया फाउंडेशन ने हार्दिक पटेल को कांग्रेस को मोहरा बताया

अहमदाबाद (ईएमएस)। भाजपा का विरोध कांग्रेस को समर्थन का संकेत दे चुके पास नेता हार्दिक पटेल की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। अहमदाबाद, जामनगर और राजकोट के कई क्षेत्रों में हार्दिक पटेल का विरोध तेज होने लगा है। इसी कड़ी में आज विश्व उमिया फाउंडेशन ने हार्दिक पटेल को कांग्रेस को मोहरा करार दे दिया। दरअसल विश्व उमिया फाउंडेशन पाटीदारों के अनेक सामाजिक कार्यों से जुड़ी संस्था है और पाटीदार भी इस संस्था का सम्मान करते हैं। बुधवार को विश्व उमिया फाउंडेशन ने प्रेस कांफ्रेंस की, जिसके संयोजक सीके पटेल समेत विभिन्न संस्थाओं के नेताओं ने हार्दिक पटेल पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हार्दिक पटेल पाटीदार समाज के भोले भाले युवकों को गुमराह कर रहा है। सरकार ने पाटीदारों की चार मांगें स्वीकार कर ली हैं, इसके बावजूद कांग्रेस के समर्थन से हार्दिक पटेल पाटीदार समाज में फूट डालने का प्रयास कर रहा है। साथ ही पाटीदार आरक्षण मांग और आंदोलन बंद कर पाटीदारों को ओबीसी में आरक्षण दिए जाने की मांग जारी रखने का ऐलान किया है। फाउंडेशन ने कांग्रेस को भी पाटीदार समाज को गुमराह नहीं करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है भाजपा के साथ नहीं जाने और कांग्रेस को समर्थन का संकेत दे चुके हार्दिक पटेल ने भी अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें ओबीसी में आरक्षण चाहिए या आर्थिक आरक्षण चाहिए या फिर ओबीसी के अतिरिक्त आरक्षण चाहिए।

बाइक समेत दंपत्ति नहर में गिरा, पत्नी की मौत

कच्छ (ईएमएस)। जिले के चोबारी गांव के निकट बाइक सवार एक दंपत्ति नर्मदा नहर में जा गिरा। इस घटना में पति बचा गया। जबकि पत्नी की नहर में डूबने से मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक कच्छ जिले की भचाऊ तहसील के चोबारी गांव स्थित नर्मदा नहर के बगल से गुजरने वाली सड़क से महेश मणवर अपनी पत्नी गीता के साथ मोटर साइकिल से जा रहा था। अचानक महेश मणवर को चक्कर आने लगा और उसका स्टेयरिंग से नियंत्रण छूट गया। जिसकी वजह से बेलगाम बाइक दंपत्ति के साथ नर्मदा नहर में जा गिरी। इस हादसे में महेश मणवर बच गया। लेकिन उसकी पत्नी गीता मणवर की नहर में डूबने से मौत हो गई। अचानक महेश मणवर को चक्कर आने लगा और उसका स्टेयरिंग से नियंत्रण छूट गया। जिसकी वजह से बेलगाम बाइक दंपत्ति के साथ नर्मदा नहर में जा गिरी। महेश और गीता की डेढ साल पहले ही शादी हुई थी।

बैंक धोखाधड़ी में कारोबारी गिरफ्तार

अहमदाबाद (ईएमएस)। प्रवर्तन निदेशालय ने पांच हजार करोड़ रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में एक कारोबारी गगन धवन को गिरफ्तार किया है। यह मामला गुजरात की एक फार्मा कंपनी और कुछ अन्य हवाला सौदों से संबंधित है। बताया जा रहा है कि गगन धवन की गिरफ्तारी के साथ जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं, उनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के रिश्तेदार का भी नाम है। हालांकि, इस संबंध में अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। धवन का नाम गुजरात की कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड केस में सामने आया था। सीबीआई ने कंपनी पर धोखाधड़ी के मामले में तमाम दस्तावेज जब्त किए थे, जिसमें गगन धवन का नाम भी सामने आया था। इस कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गगन धवन को बुधवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। धवन को हिरासत के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि आपराधिक शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय धवन द्वारा आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्वत देने के कथित आरोपों की जांच कर रहा था। उसने अगस्त में दिल्ली में धवन और एक पूर्व कांग्रेस विधायक के परिसरों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने हाल में स्टर्लिंग बायोटेक और उसके निदेशकों चेतन जयंतीलाल संदेसरा, दीप्ति चेतन संदेसरा, राजभूषण ओमप्रकाश दीक्षति, नितिन जयंतीलाल संदेसरा और विलास जोशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हेमंत हाथी, आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तासीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) **E-mail: krantisamay@gmail.com**